पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं

वैभव न्यूज ■ मालीगांव

बिजलीकरण, माल लोडिंग, समय की पाबंदी और बुनियादी संरचना के विकास में नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (पू. सी. रेलवे) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। उल्लेखनीय प्रगति का प्रदर्शन करते हुए, पू. सी. रेलवे ने वर्ष 2024-25 में 1,141.388 रूट किलोमीटर (आरकेएम) और 1,502.743 ट्रैक किलोमीटर (टीकेएम) का बिजलीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर चालू किया, जिससे यह किसी भी एक वित्तीय वर्ष में हासिल किया गया अब तक का सर्वाधिक होने वाला बिजलीकरण है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि रेल परिचालन को आधुनिक बनाने और दक्षता में सुधार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। माल परिवहन में, पू. सी. रेलवे ने माल लोडिंग में 4.21त्न की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2023-24 में 10.24 मिलियन टन (एमटी) माल लोडिंग की गई, जो 2024-25 में बढ़कर 10.67 एमटी हो गया। माल ढुलाई आय पिछले वर्ष 1,201.224 करोड़ रुपये की तुलना में 2024-25 में 1,299.643 करोड़ रुपये हासिल हुआ, जो साल-दर-साल 8.19त्न की निरंतर वृद्धि है। इस रेलवे ने वर्ष 2024-25 में 1,380 रेकों की आपूर्ति कर अपना सर्वश्रेष्ठ पेट्रोलियम, ऑयल और लुब्रिकेंट्स (पीओएल) लोडिंग भी हासिल किया। इसके अतिरिक्त, पू. सी. रेलवे ने ट्रेन के समय-पाबंद में उल्लेखनीय प्रगति की और वर्ष 2024-25 के दौरान 80.68प्र. के समय-पाबंद के प्रदर्शन के साथ सभी जोनल रेलवे में 7वां सर्वोच्च स्थान हासिल किया। यात्रियों की सुविधा बढ़ाने के लिए, पू. सी. रेलवे ने आठ नई ट्रेन सेवाएं शुरू कीं, चार जोड़ी मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों का विस्तार किया और चार ट्रेनों की आवृत्ति बढ़ाई। इसके अलावा, सात ट्रेनों को सात स्टेशनों पर नए ठहराव प्रदान किए गए और 46 ट्रेनों की गति में सुधार करके 930 मिनट बचाए। यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए, 16 ट्रेनों में स्थायी तौर पर 40 अतिरिक्त कोच जोड़े गए। स्पेशल ट्रेन सेवाओं में भी वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2024-25 में 1,430 फेरों का परिचालन किया गया।

हेमंत ने पेड़ लगाकर प्रकृति से जुड़े रहने का दिया संदेश

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरहुल पूजा महोत्सव में हुए सम्मिलित

वैभव न्यूज ■ रांची

पर्व त्योहारों से हमारी परंपरा, सभ्यता-संस्कृति और आस्था जुड़ी है। इससे जीवन मे उमंग, उत्साह तथा उल्लास का संचार होता है। इसी कड़ी में हम सालों- साल से परंपरानुसार सरहुल पर्व मनाते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने इस प्रकति पर्व की परंपराओं को अक्षुण्ण एवं मजबूती दी है। हमें विरासत में मिली इस परंपरा को और आगे ले जाना है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर, करमटोली, रांची में आयोजित सरहुल पूजा महोत्सव में छात्र-छात्राओं को संबोधित कर रहे थे। इस पावन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री ने यहां पारंपरिक विधि विधान से पूजा- अर्चना कर राज्य के विकास, सुख- समृद्धि एवं शांति की कामना की। मुख्यमंत्री ने परिसर में वृक्षारोपण कर (सखुआ का वृक्ष लगाकर) प्रकृति से जुड़े रहने का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य वासियों को सरहुल महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि झारखंड के बेहतर भविष्य के लिए आने वाले 25 वर्षों को ध्यान में रखकर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी कॉलेज छात्रावास परिसर में हर वर्ष धूमधाम से सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मुझे यहां आयोजित सरहुल महोत्सव में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यहां आकर आप सभी के साथ खुशियों को बांटने का मौका मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यहां हम प्रकृति को संरक्षित रखने और अपनी परंपराओं को लेकर आगे बढ़ने का एक संकल्प लेते हैं। हमारा संकल्प पूरा हो, इस दिशा में हमें सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारी जिंदगी काफी व्यस्त हो चुकी है। लोगों के पास वक़्त कम है, फिर भी विरासत में मिली अपनी परंपरा एवं सभ्यता- संस्कृति से जुड़े रहने के लिए वक़्त जरूर निकालें। यह हमारी आने वाली पीढ़ी की बेहतरी के लिए जरूरी है। इससे आपसी रिश्ते मजबूत होते हैं और पर्व- त्योहारों का जश्न मिलकर मनाने की अलग ही खुशी मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों को बेहतर व्यवस्था देने के लिए सभी छात्रावासों का जीर्णोद्धार हो रहा है। इस कड़ी में आदिवासी कॉलेज छात्रावास, करमटोली और महिला कॉलेज छात्रावास में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाई जाएगी। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे सिर्फ अपनी पढ़ाई की चिंता करें, बाकी सारी व्यवस्था सरकार करेगी। आप सही दिशा में आगे बढ़े, सरकार आपके साथ खड़ी है। कृषि मंत्री शिल्पा नेहा तिर्की एवं विधायक कल्पना सोरेन ने भी पारंपरिक विधि- विधान से पूजा-अर्चना कर राज्य के विकास तथा खुशहाली की कामना की।

इंदौर में भूख के कारण हिंसक हो रहे आवारा कुत्ते

वैभव न्यूज ■ इंदौर

देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में साफ-सफाई का एक दुष्प्रभाव करीब ढाई लाख आवारा कुत्तों के लिए भोजन के संकट के तौर पर सामने आया है। जानकारों के मुताबिक, भोजन की यह समस्या इन जानवरों के हिंसक स्वभाव की प्रमुख वजहों में शुमार है। यह बात ऐसे वक्त सामने आई है, जब शहर में आवारा कुत्तों के लोगों को काटने की बढ़ती घटनाओं के बीच स्थानीय प्रशासन इन जानवरों की नसबंदी के अब तक के सबसे बड़े अभियान की तैयारी में जुटा है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि प्रशासन ने तय किया है कि शहर में आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए छह महीने का विशेष अभियान चलाया जाएगा ताकि उनकी तादाद को नियंत्रित किया जा सके। नगर निगम में पशु जन्म नियंत्रण (एबीसी) कार्यक्रम के प्रभारी डॉ. उत्तम यादव ने पीटीआई-भाषा को बताया, शहर में आम तौर पर हर रोज 30 से 35 आवारा कुत्तों की नसबंदी होती है। हमने इस संख्या को बढ़ाकर 90 पर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है। इसके लिए मानव संसाधन और अन्य सुविधाओं में इजाफा किया जा रहा है। यादव ने माना कि भूख के कारण शहर के आवारा कुत्ते चिड़चिड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा, कुछ बरसों पहले शहर में कचरा यहां-वहां पड़ा रहता था और बड़ी कचरा पेटियां भी रखी होती थीं। आवारा कुत्ते इनमें अपना भोजन ढूंढ़ लेते थे, लेकिन अब शहर में कचरा पेटियां नहीं हैं और नगर निगम की गाड़ियों से हर घर और प्रतिष्ठान से कचरा जमा किया जाता है। इससे आवारा कुत्तों को आसानी से भोजन नहीं मिल पा रहा है। एबीसी कार्यक्रम के प्रभारी ने कहा कि आवारा कुत्तों को भोजन की तलाश में अपना इलाका छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना पड़ता है जिससे अन्य कुत्तों के साथ उनके हिंसक संघर्ष होते हैं और कई बार इससे तनावग्रस्त होकर भूखे कुत्ते आम लोगों को काट लेते हैं। यादव ने कहा कि कोविड-19 के प्रकोप के चलते हुई तालाबंदी के दौरान स्थानीय प्रशासन ने आवारा कुत्तों के लिए भोजन का इंतजाम किया था, लेकिन अब शहर में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा, हमने आवारा कुत्तों को भोजन बांटने के लिए कुछ गैर सरकारी संगठनों और पशुप्रेमियों को अधिकृत करते हुए उन्हें फीडर कार्ड बांटे हैं ताकि इन जानवरों को खाना मिलता रहे और भूख के कारण उनमें चिड़चिड़ाहट कम हो। यादव ने मोटा अनुमान जताया कि नगर निगम सीमा में करीब ढाई लाख आवारा कुत्ते हैं।

सुविधा स्टोर को 24 घंटे खुले रहने से नहीं रोकता कानून

मुंबई। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि चौबीस घंटे खुली रहने वाली किराना दुकानें ग्राहकों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के लिए भी फायदेमंद हैं और कानून के तहत उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अदालत ने पुणे पुलिस को निर्देश दिया कि वह किसी दुकान को रात 11 बजे तक बंद करने के लिए बाध्य न करे। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने कहा कि 24 घंटे एवं सातों दिन सुविधा स्टोर की अवधारणा दुनिया भर में लोकप्रिय है। उन्होंने बताया कि फैसले में कहा गया, इससे उपभोक्ताओं को खरीदारी करने में सुविधा, आसानी और लचीलापन मिलेगा, विशेषकर उन लोगों को जिनके काम के घंटे असामान्य होते हैं। अदालत ने कहा, ऐसा माना जाता है कि इससे उपभोक्ता खर्च में वृद्धि के साथ-साथ अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, जो हमारे जैसे बड़े देश के लिए महत्वपूर्ण है, जहां बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है। पीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि इन लाभों को स्वीकार करते हुए तथा वैश्विक मानकों के अनुरूप प्रगति हासिल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा ऐसे स्टोर के संचालन के समय पर कोई पाबंदी नहीं लगा ई गई है। यह आदेश एक्सेलरेट प्रोडक्ट्स वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका पर आया, जो पुणे के हडपसर क्षेत्र में द न्यू शॉप चलाती है। याचिका में दावा किया गया कि स्थानीय पुलिस अवैधानिक और मनमाने तरीके से कंपनी को रात 11 बजे तक दुकान बंद करने के लिए कह रही है, उन्होंने बताया कि जबकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई सुविधा स्टोर रात में संचालित नहीं हो सकता।

हम तो पूछेंगे, जवाब दे आरजेडी: जदयू

वैभव न्यूज ■ पटना

जद (यू0) प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा, प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया और पार्टी मीडिया पैनलिस्ट पूजा एन शर्मा ने संयुक्त तौर पर मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार के कामों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार का मॉडल अनूठा है और वो महिलाओं को राजनीतिक,सामाजिक और आर्थिक तौर पर सशक्त करने को लेकर एक रोल मॉडल हैं। उन्होंने कहा कि देश की पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने भी महिला सशक्तिकरण को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों की जमकर तारीफ की थी और उसे बेहतरीन बताया था। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ताओं ने साल 1990 से लेकर 2005 तक आरजेडी ने अपने शासनकाल के दौरान बेटियों के सशक्तिकरण को लेकर क्या-क्या काम किए इन सवालों के क्रमवार जवाब मांगने की बात कही।

आरजेडी से सवाल -:

1. जब 2006 में नीतीश कुमार सरकार ने 'मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना' और 'पोशाक योजना' शुरू कीं, तब लड़कियों की स्कूल जाने की संख्या में भारी बढ़ोतरी देखी गई। आरजेडी शासन में ऐसी योजनाएं क्यों नहीं बनीं?
2. बिहार में बेटियों की उच्च शिक्षा को लेकर कॉलेजों की संख्या बढ़ाने, छात्राओं के लिए छात्रावास और अन्य सुविधाएं देने में आरजेडी सरकार की क्या भूमिका थी?
3.बालिकाओं को इंटरमीडिएट/स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आर्थिक सहायता देकर उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने का विचार आपके शासनकाल में क्यों नहीं किया गया?
4. आपके शासनकाल (1990-2005) में महिला अभ्यर्थियों को सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए प्रोत्साहित करने और सहायता देने के लिए कोई योजना क्यों नहीं बनाई गई?
5.आरजेडी के शासनकाल (1990-2005) में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई ठोस योजना क्यों नहीं बनाई गई? नर्सिंग और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना जैसे प्रयास आरजेडी के कार्यकाल में क्यों नहीं किए गए?

पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा कि आरजेडी को बेटियों की शिक्षा से जुड़े सवालों पर तार्किक जवाब देना चाहिए अन्यथा ये माना जाएगा कि राजद शासनकाल में बेटियों की शिक्षा और उनका उत्थान उनकी प्राथमिकता नहीं थी।

मुंबई सेंट्रल मंडल ने 105 लेवल क्रॉसिंग बंद करने की उपलब्धि हासिल की

वैभव न्यूज ■ मुंबई

पश्चिम रेलवे अपने यात्रियों को सुरक्षित और आरामदायक यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल ने पिछले 5 वर्षों में 105 लेवल क्रॉसिंग बंद करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसमें इंटरलॉक्ड और नॉन-इंटरलॉक्ड दोनों क्रासिंग शामिल हैं। रेलवे पर लेवल क्रॉसिंग बंद करने से कई लाभ होते हैं, जिसमें सड़क और रेल संरक्षा में वृद्धि, कंजेशन कम करना, दुर्घटनाओं में कमी, ट्रेन की गति में वृद्धि और समयपालनता में सुधार के साथ-साथ समग्र रूप से सुचारू रेल परिचालन और दक्षता शामिल है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक द्वारा के अनुसार, पश्चिम रेलवे के मुंबई सेंट्रल मंडल ने पिछले 5 वर्षों में 105 लेवल क्रॉसिंग बंद करके संरक्षा बढ़ाने में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की है। रेलवे पर लेवल क्रॉसिंग बंद करने से कई लाभ होंगे, जिनमें शामिल हैं संरक्षा लाभ लेवल क्रॉसिंग बंद करने से ट्रेनों और सड़क वाहनों के बीच टकराव की संभावना को समाप्त करके दुर्घटनाओं, चोटों और जानमाल की हानि के जोखिम को काफी हद तक कम किया गया है। लेवल क्रॉसिंग बंद करने से दुर्घटनाओं के जोखिम को दूर करके सार्वजनिक संरक्षा में वृद्धि हुई है, जिससे परिवारों और समुदायों पर भावनात्मक और आर्थिक प्रभाव कम हुआ है। यातायात और कंजेशन से संबंधित लाभ लेवल क्रॉसिंग को बंद करने से ट्रैफिक कंजेशन में काफी कमी आई है, खासकर मुंबई-वडोदरा-दिल्ली सेक्शन जैसे व्यस्त मार्गों पर, जहाँ वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी एक्सप्रेस जैसी हाई-स्पीड ट्रेनें चलती हैं। लेवल क्रॉसिंग को खत्म करने से यातायात प्रवाह में सुधार होता है,कंजेशन कम होती है और ट्रेनों को 160 किमी प्रति घंटे तक की उच्च सेक्शनल गति प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। लेवल क्रॉसिंग को बंद करने से वाहनों को रुकने की आवश्यकता नहीं होने से यातायात दक्षता में वृद्धि होती है, जिससे यात्रा का समय कम हो जाता है। ट्रेन सेवाओं को तेजी से बढ़ाने, जनता की मांग को पूरा करने और समग्र यातायात प्रबंधन को बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है। आर्थिक लाभ लेवल क्रॉसिंग को बंद करने से लेवल क्रॉसिंग के बुनियादी ढांचे को बनाए रखने, अपग्रेड करने और आधुनिक बनाने से जुड़ी लागतों में बचत हुई है।

असम में सभी उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में कटौती की घोषणा: मुख्यमंत्री शर्मा

वैभव न्यूज ■ गुवाहाटी

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने मंगलवार को राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में एक रुपए प्रति यूनिट की कटौती की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के अंत में बिजली दरों में और कटौती की घोषणा की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि जीवन धारा और हाई टेंशन सहित सभी श्रेणियों के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली शुल्क में एक रुपए प्रति यूनिट की कटौती की जाएगी। उन्होंने बताया कि अन्य सभी श्रेणी के ग्राहकों के लिए 0.25 रुपए प्रति यूनिट की कटौती की जाएगी। शर्मा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अप्रैल आ गया। तापमान बढ़ेगा, लेकिन आपका बिजली बिल कम होगा। उन्होंने कहा, आज (मंगलवार) से असम में परिवारों को बिजली बिल में। रुपए प्रति यूनिट की कमी देखने को मिलेगी, साथ ही वर्ष के अंत में छूट भी मिलेगी। मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने अपने पोस्ट में एक मुस्कुराता हुआ इमोजी डालते हुए कहा, यह अप्रैल फूल के नाम पर कोई मजाक नहीं है। बिजली दरों में कटौती का प्रस्ताव राज्य के वार्षिक बजट में रखा गया था, जिसे पिछले महीने विधानसभा में पारित किया गया था। शर्मा ने पहले भी संकेत दिया था कि वर्ष के अंत तक दरों में और कमी की जाएगी।

मध्यप्रदेश के सभी सीएम राइज स्कूल का नाम सांदीपनि विद्यालय होगा: मुख्यमंत्री मोहन यादव

वैभव न्यूज ■ भोपाल

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य में सीएम राइज स्कूलों का नाम सांदीपनि विद्यालय होगा। यह नाम हिंदू पौराणिक कथाओं के सांदीपनि आश्रम से प्रेरित है। यादव यहां एक शैक्षणिक संस्थान में स्कूल चले हम अभियान के तहत राज्य भर के सरकारी स्कूलों में प्रवेश शुरू करने के लिए राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम-2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण ने सांदीपनि आश्रम में शिक्षा प्राप्त की थी। इसलिए, सीएम राइज स्कूलों का नाम सांदीपनि के नाम पर होना चाहिए। अब राज्यभर में इन स्कूलों का नाम आचार्य सांदीपनि के नाम पर रखा जाएगा और इन्हें सांदीपनि विद्यालय कहा जाएगा। यादव ने कहा कि भगवान कृष्ण ने कंस के कुशासन का अंत किया और शिक्षा के महत्व का प्रचार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे खुद सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे कलाम जिन्हें भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता था, पूर्व राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सहित कई महान हस्तियों ने भी सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है। यादव ने कहा कि सरकार छात्रों को कोचिंग, स्कूली वर्दी, लैपटॉप, साइकिल और स्कूटर मुहैया करा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में राज्य शिक्षा के क्षेत्र में विकास कर रहा है। इससे पहले, यादव ने स्कूल में लड़कियों का स्वागत किया और केजी-2 कक्षा में उनके प्रवेश की औपचारिकताएं पूरी कीं और उन्हें उपहार दिए। मुख्यमंत्री ने स्कूलों में प्रवेश के लिए राज्य शिक्षा विभाग के एक पोर्टल का भी शुभारंभ किया।

ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कटक जिले में आयोजित ओडिशा दिवस समारोह मे संबोधित किया

आयुष्मान योजना अगले दो हफ्ते में लागू होगी: माझी

वैभव न्यूज ■ भुवनेश्वर

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य में आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अगले दो हफ्ते में लागू कर दी जाएगी। कटक जिले में आयोजित ओडिशा दिवस समारोह में माझी ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले इस योजना को एक अप्रैल को गोपबंधु जन आरोग्य योजना के साथ लागू करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में इसके क्रियान्वयन की तारीख बदल दी गई। हालांकि, मुख्यमंत्री ने तिथि में बदलाव की वजह नहीं बताई। उन्होंने दावा किया कि राज्यभर में करीब 3.52 करोड़ लोग इस स्वास्थ्य योजना के दायरे में आएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को देशभर के 29,000 अस्पतालों में नकदी रहित इलाज की सुविधा मिलती है। माझी ने कहा कि इस योजना में सिर्फ ओडिशा ही नहीं, बल्कि राज्य के बाहर के अस्पताल भी शामिल होंगे और वे जरूरत पड़ने पर विशेष देखभाल भी प्रदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि ओडिशा की पिछली बीजू जनता दल (बीजद) सरकार ने राज्य में आयुष्मान भारत योजना को लागू करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, ग्रामीण समुदायों और अन्य लोगों को लाभ मिलेगा, जो महंगी चिकित्सा देखभाल का खर्च उठाने में संघर्ष करते हैं। माझी ने कहा कि पिछली बीएसकेवाई (बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना) में जहां केवल 900 अस्पताल शामिल थे, वहीं आयुष्मान भारत योजना के दायरे में 29,000 अस्पताल आते हैं।

पालघर में नदी में बोरे में बंद महिला का शव मिला

पालघर। महाराष्ट्र के पालघर जिले की एक नदी में मंगलवार को एक अज्ञात महिला का शव बोरे में बंद मिला। पुलिस ने यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि ग्रामीणों ने नासिक-मोखाडा-जव्हार रोड पर घाटकरपाड़ा में वाघ नदी में एक बोरा तैरता हुए देखा था, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम को बोरे में एक महिला का सड़ा-गला शव मिला। उसकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है। अधिकारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस घटना के संबंध में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1)(हत्या) और 238 (साक्ष्य मिटाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि महिला की गला घोंटकर हत्या की गई और उसके शव को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया गया।

मोपा एयरपोर्ट और डोडामार्ग: गोवा के विकास का भविष्य

वैभव न्यूज ■ गोवा

मोपा और डोडामर्ग व्यापार और अवकाश दोनों के लिए प्रमुख गंतव्य बनने के लिए तैयार हैं।

मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के आसपास का विकास उत्तरी गोवा और डोडामार्ग को पर्यटन, व्यवसाय और रियल एस्टेट के लिए एक संपन्न केंद्र में बदलने के लिए तैयार है। सड़क नेटवर्क, राजमार्गों और बुनियादी ढांचे में बड़े निवेश के साथ, यह क्षेत्र तेजी से विकसित हो रहा है, निवेशकों, डेवलपर्स और व्यवसायों को आकर्षित कर रहा है। मोपा के पास स्थित डोडामार्ग एक रियल एस्टेट हॉटस्पॉट के रूप में उभर रहा है, जो प्रतिस्पर्धी कीमतों पर प्लॉटेड डेवलपमेंट, लक्जरी विला और वाणिज्यिक स्थान प्रदान करता है। हवाई अड्डे से इसकी निकटता और सुंदर परिवेश इसे निवेश के लिए एक प्रमुख स्थान बनाते हैं। एक प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर फर्म के ग्लोबल सेल्स हेड आशीष डे के अनुसार, कई हाई-प्रोफाइल प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, जिनमें एक विश्व स्तरीय कैसीनो और मनोरंजन केंद्र, एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और कॉर्पोरेट कार्यालयों, होटलों और खुदरा केंद्रों के साथ एक एयरोसिटी शामिल है, जो न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा बल्कि कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। बेहतर कनेक्टिविटी, बड़े पैमाने पर निवेश और तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट बाजार के साथ, मोपा और डोडामर्ग व्यापार और अवकाश दोनों के लिए प्रमुख गंतव्य बनने के लिए तैयार हैं, जो भविष्य में गोवा के विकास को गति देंगे।